1247

### EDUCATION DEPARTMENT

#### The 11th July, 1984

No. 50/3/84-EDUI (7).—The Governor of Haryana is pleased to constitute a Publication Committee for the Haryana Sahitya Academy comprising the following:—

- 1. Deputy Secretary/Joint Secretary to Government, Haryana, Education Department.
- 2. Controller of Printing and Stationery, Haryana.
- 3. Director, Haryana Sahitya Academy.
- 2. The Committee shall lay down general policies and guidelines for the work relating to publication of books such as selection of presses, fixation of rates of printing, purchase of paper etc., for the Haryana Sahitya Academy.
- 3. The terms of the Committee will be for three years, but the Government may, by express order, reconstitute or dissolve the Committee, as and when they so desire.
  - 4. The Committee shall meet at least once in a year.
  - 5. The Headquarters of the Committee will be at Chandigarh.
- 6. The members of the Committee shall draw their T.A./D.A., if any in connection with the meetings of the Committee from their respective Departments.

# L. M. JAIN,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Education Department.

### श्रम विभाग

## दिनांक 6 प्रगस्त, 1984

सं श्रो विव /एफ वो ०/61-84/28376 चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं असुपरटेकस प्लाट नं 39, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

श्रीर चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णाय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रब, घोँचोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अर्धान गटित, घाँचोगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे दिनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रिमकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं भथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामले हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :---

- 1. क्या श्रमिक दो जोड़े पैंट, शर्ट तथा एक जोड़ा जूता (बाटा) लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
- 2. वया श्रमिक वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 का 20 प्रतिशत की दर सै बोनस के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

मीरां सेठ,

वित्तायुक्त एवं सिचव, हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग।

#### दिनांक 31 जुलाई, 1984

सं भी. बि. पानीपत 9/84/27551. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सुपर रवड़ इन्टरप्राइजिज, 17/3 माईल स्टोन, जी. टी. रोड, करनाल, के श्रीमिक श्री दमन लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामने में कोई ग्रीबोगिक विवाद है:

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांक्रनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद मिन्नियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मिन्नियूचना सं. 3(44)%-3-3-अम, दितांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अ जाता, को विद्यादयस्त या उससे मस्विम्यत तोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादयस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संवन्धित मामला है:—

क्या श्री चंदन जाल की <mark>सेवाश्रों का समापन न्यायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का</mark> इकदार है ?

मं. प्राः वि/पानीपत/ः 0 84/27557.—चूंकि हरियाणा को राज्यपता हो ए र है िर्मेठ मुपर रचा उन्टरप्राईदिल 17/3 माईत स्टोन, जो: टंट रोड, करनाल, हे श्रमिक श्रा लाल बहादुर तथा उनके प्रबन्धकों के कथ्य इनमें उसके कदा तिहार मामने में कोई श्रोबोगिक विरोद है ,

भी जें. कें र मा है राज्यपात विकाद की स्वायतिर्णय हेत निविध्य करना हांछतीय समसते हैं :

्याँ गए, अब, बौबोगिक विवाद प्रधिनिथम, 1947 को आरा 10 को उपधार (1) हे खण्ड (ग) द्वार प्रदान की गई शिवन्यों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यकाल इस के द्वारा सरकारी अधिमूचन सक 3(44) इ.-3-थम, दिनाक .9 द्वारील, 1984 इ.ए. कात प्रधिनियम को बारा 7 के अबीन गठित अस न्याकलय, प्रम्बाल का विवाद प्रस्त पा उपने सूनीक या उनसे सम्यन्तित नीचि कि मानार वायनिर्णय के निए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उपन प्रयन्त्रकों तथा थामिल के बीच का भी विवाद प्रस्त मामला है था विवाद ने सुनीक प्रथम प्रयन्तित नीचि कि विवाद ने सुनीक प्रथम मामला है ।——

क्या धा लाल बहाद्र को सेवाओं का समापन न्यापोचित तथा ठोक है है यदि कहीं, तो पह किए अहर का हत्यार हे है

सं. औं.वि./पानी 'त्/ ां, 84/27563.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि मैं. नुगर रपड़ इन्टरप्राईजिज. 17/3 माईल स्टोन, जी टी. रोड, करनाल, के श्रमिक श्रो जय पान तथा उसके प्रवस्थकों के मध्य ाममें इसके बाद लिखित मामले में कोई धौद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

्सिलिए अब श्रीद्योगिक विवाद श्रीद्यित्यम 1947, को बारा 10 को उपधारा (1) के ल्एड (ग) द्वारा प्रदान को गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रीधमूचना सं० 3(4-)-8 -3-अम. दिनांक 19 श्रप्रेल, 198-4 द्वारा उक्त प्रिवित्याम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्वाला, को विवादग्रस्त वा उमसे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रमवा संबंधित मामला है:--

क्या श्री जय पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठील है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ?

मं. ब्रो.वि/एफ. डी./114-84/27571.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि जै० परके हसन टर्नो इन्हीनियर्स, 14/4, मथूरा रोड, फरीदाबाद के अभिक श्री जगरामपाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके गद लिखित मामले में कोई भौजोगिक विवाद है;

भीर वृंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना बांछनीय समलते हैं :

इसलिए, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई मिनस्यों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिमृत्तनः पं० 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिस्त्वनां स० 1:435-जी-धम-57/1124ई/दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उन्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय. फरोदाद्याद की विवादयस्त या उन्नसे सुखंगत या उन्नसे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्देष्ट करते हैं जो कि उन्त अबन्धां तथा श्रमिक के बीच या तो विवादयस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जगराभपाल की सेवा**र्कों का समापन त्यायोधित तथा ठीक** है ? यदि नहीं, से वह किम रहि। का हक**दा**र है ?

एस० के० महेश्वरी, संयुक्त पर्वेक, इत्यिया सरकार, श्रम विभाग ।